लोकतंत्र के लिये घातक दिशाविहीन नक्सलवादी आंदोलन का विवेचनात्मक अध्ययन

*डॉ. (श्रीमती) रीमा रानीदास

शोधपत्र-राजनीति शास्त्र

प्रारम्भ से ही व्यक्ति और राज्य के सम्बंध जटिल थे हैं, मानव जीवन की सरलता के साथ राजय का स्वरूप भी सरल था, किन्तु मानव जीवन की जटिलता से राज्य का स्वरूप परिवर्तित हुआ जिसके कारण राज्य और वयक्ति के सम्बधो में जटिलता आने लगी राज्य व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करता है, समाज द्वारा स्वीकृत, तब मानव का कर्त्तव्य बनता है कि अधिकारों का उपयोग करते हुये अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक भारत के सामने अनेक चुनौतियॉं थी समस्या के रूप में, लोकतंत्र को सम्पुर्ण रूप देने के लिये आवश्यक था कि उसका राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रर्याप्त रूप में विकास हो, इसी सामाजिक आर्थिक कारणों से पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र 1967 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, इसके प्रणेता चारू मजमूदार थे यह आंदोलन भूम्वासियों के शोषण के विरूद्व खेतिहार वर्ग का विरोध था।

इन्होनें शातिपूर्ण साधन को नही अपनाया बल्कि यह सशस्त्र आंदोलन था, नक्सलवाडी क्षेत्र के तीर धनुषाधारी संथालों ने मुल्क की भूमि पर कब्जा किया, हल चलाया भण्डार किये गये धान रखने वाले घरों का समक्ष प्रदर्शन किया। स्टॉक छीने, इस मामले में झड़पे हुई सरकार ने हिचकिचाकर इस मामले पर कार्यवाही कर इसे दबाया चीन में माओवादी पार्टी का गठन हुआ, नक्सलवादी भी इस विचारधारा से प्रभावित हुये नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार व कनु सन्याल के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगा, चारू मजूमदार का नारा था ''सघर्ष कही भी और विस्तार करो'' इसका प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, एवं आंध्रप्रदेश के कुछ भागों तक सीमित था, 1970 तक कुछ समय पश्चात यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ समय पश्चात यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक फैल गया, सरकार ने सेना की सहायता से इसके विरूद्व संयुक्त अभियान शुरू किया, यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त 1971 तक चला, इस अभियान को नाम दिया गया 'ऑपरेशन स्टीपल्वेंज' का। इसमें आने जाने मार्ग को बन्द कर बाहरी घेरे पर सेना व आंतरिक घेरे पर रिजर्व पुलिस बल तैनात किये जाते है। पीपुल्स वार ग्रुप(पी.डब्लू.जी) जिसका प्रभाव व वर्चस्व उत्तरी पश्चिमी तेलगांना, पूर्वी महाराष्ट्र और पश्चिमी उड़ीसा था। इसी के समान दूसरा गुट माओइस्ट (कम्युनिस्ट सेन्टर ऑफ इंण्डिया) (एम. सी.सी.आई) जो मध्यभार सक्रिय था। पी. डब्लू.जी. और एम.सी.सी. आई का 2004 में विलय हो गया और माकपा (माओवादी) के रूप में संगठित होकर आया, आंध्रप्रदेश के प्रमुख क्रान्तिकारी मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति इस दल के महासचिव है, जनवरी 2007 के उत्तराद्वं में जंगल मे एकता कांग्रेस की सभा हुयी जिसमें माआंवादियों के प्रमुख राजनैतिक और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया। इस माओवादी दल ने वही रास्ता अपनाया, जो 1930 के दशक में चीन के नेता माओत्से तुंग ने अपनाया था चीनी क्रान्ति के समय था। माओवादी नेता गणपति उपनेता दलीय सर्कुलर में कहते है कि ' जब हमने संघर्ष शुरू किया था, तो यह जमीन अजीविका जैसे जनमुद्दों तथा सामंती एवं साम्राज्यवादी शोषण एवं दमन से मुक्ति से जुड़ा एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन जब शांतिपूर्ण मार्च, रैलियों धरनों, भूख हड़ताओं और आम हड़तालों की अनदेखी की गई या उन्हें कुचलने की कोशिश की गई तो, लोगो को हिंसक तरीका उपनाने पर मजबूर होना पड़ा।'' आन्ध्रप्रदेश में 1980 में कोंडापल्ली सीमारमैयाने पीपुल्स वार गान द्वारा इस नक्सली आंदोलन को आगे बढ़ाया 1987 के आते आते पीपुल्स बार ग्रुप ने सांस्कृतिक संगठन जन नाट्य मंडली का गठन किया , इसमें नेता गुम्माड़ी विट्ठल राव अपने गीतो (नक्सलवादियों) के माध्यम से सरकार के कार्य को प्रभावित करने लगे। इसका प्रभाव, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश उड़ीसा के अतिरिक्त कर्नाटक व तमिलनाडु पर पड़ा।

बिहार में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एस.सी.सी) सक्रिय था इसने अनेक हिंसात्मक गतिविधियॉ की, इसकी शाखायें मध्यवर्ती जिलों तक फैल गयी है। 1987 से 1992 तक चतरा और औरंगाबाद जिलों में बड़ी वरदातें हुईं। जिसका उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक न्याय था जो बाद मं जातीय संघर्ष में परिवर्तित हो गया। जिससे बिहार व झारखण्ड क्षेत्र में वैमनस्य और हिंसा फैलने लगा नवम्बर 2000 में झारखण्ड को पृथक राज्य बनाया गया, तब माओवादी कम्युनिस्ट का केन्द्र झारखण्ड बन गया। झारखण्ड के 22 में से 15 जिलों पर नक्सलवाद का

* सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शा. डी. के. महाविद्यालय बलौदाबाजार, रायपुर

फैलाव हुआ मध्यप्रदेश में नक्सली हिंसा का प्रभाव क्षेत्र बालाघाट मंडला, डिंडोरी, व सीधी जिला है। चार बड़े पीपुल्स वार ग्रुप की हत्या का बदला लेने के लिये 15 दिसम्बर 1995 में लखीराम कावड़ेन राज्य परिवहन मंत्री की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने 1980 के दशक मे दंडकारण्य आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महारष्ट्र के विशालकाय वनों के क्षेत्र मे प्रवेश कर किसानों को एकजुट कर एक ग्रामीण वर्ग विहीन समाज की कल्पना की।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद:—छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद का फैलाव पृथक राज्य बनाने से पहले कुछ बस्तर, राजनांदगॉव, जशपुर, सरगुजा तक था। 01 नवम्बर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात नक्सली वारदातों के क्षेत्र में वृद्धि हुई, नक्सली प्रभाव क्षेत्र—राज्य के उत्तर में सरगुजा, पश्चिम मे राजनॉदगॉव, दक्षिण में बीजापुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण पूर्व में बस्तर, व उत्तर पूर्व मे जशपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक अस्तित्व में आने से पहले 1969 मद्देढ़ थाना में नक्सलियों के विरूद्ध पहला मामला दर्ज हुआ, 1984 में नारायणपुर के ताड़वायलली में नक्सली नेता गणपति को मारने के बाद पुलिस से नक्सलियों की शत्रुता बड़ी। 1997 में पहला बारूदी सुरंग विस्फोट फरसगॉव थाना क्षेत्र के बंगोली में नक्सलियों ने किया, जिसमें पुलिस के पॉच जवानों सहित आठ नागरिक मारे गये। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात 2004 के आस पास नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हुई। नक्सली एम्बुश सुरक्षा बलों के लिये प्रमुख चुनौती हैं।

नक्सली गतिविधियॉ है :— बारूदी सुरंग, बुबीटेप्स, क्लेमोर सुरंग, लांचर मारना, छिपकर घात करना गोरिल्ला प्रद्धति घात लगाना आदि। नक्सली दो प्रकार से एम्बुश लगाते है। (01) इंतजार का एम्बुश(02) चारा एम्बुश सुरक्षा बल के जाने के मार्ग पर इंतजार करना, दूसरा, जिस प्रकार से मछली पकड़ने के लिये चारा डालते हैं। वैसे ही चारा एम्बुश है। सुरक्षा बलो के प्रशासनिक तंत्र को अस्त व्यस्त करना नक्सलियों की गतिविधियों का प्रमुख कार्य है। जिससे नागरिकों में भी भय व्याप्त होता जाता है। 2004 में पीपुल्स बार और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के बाद माकपा माओवादी का गठन हुआ इस कारण नक्सली (माओवादी) कहलाते है। नक्सलियों ने लम्बी लड़ाई की योजना बनायी है, उनके शस्त्र है, राइफल, पिस्टल और देशी कट्टों के अलावा ए. के. 47, एवं लाइटमशीन गन जैसे घातक शस्त्र है। पुलिस के पास इस बात का भी प्रमाण है कि नक्सलियों के पास रॉकेट लॉचर है। 2006 में 2009 के आस पास इन चार वर्षो में नक्सलियों ने लगभग 13 लोगों की हत्या की, नक्सलियों के उत्पात के कारण 1296 पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों की हत्या हुई, इसमें मारे गये अन्य गोपनीय सैनिक एवं सरकारी कर्मचारी सम्मिलित नही है। 2005 से अब तक 360 पुलिस कर्मियों, 143 (एस.पी.ओ.) तथा 793 आम नागरिकों की हत्या हुई मारे गये नक्सलियों की संख्या की 281 एवं 637 बंदी बनाये गयें, धमतरी मे नक्सलियों ने पुलिस वाहन को बम द्वारा उड़ाया, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व बल के 12 पुलिस कर्मी एवं 13 लोगों की मृत्यु हुई। राजनांदगॉव जिले में दो जवानों की गोलीमारकर हत्या सी.पीएफ. के 11 जवान शहीद हुये 11 अन्य घायल हुये मैनपुर थाने में रंनू सूरज सहित 30—35 लोगो के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया। जबकि नक्सलियों ने इस वारदात के बाद जता दिया कि वे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से दूर नहीं हैं। सलवा जुडुमः— सलवा जुडुम का विचार वामपंथ को छोड़ने वाले विधानसभा में मुख्य विपक्ष के काग्रेसी नेता महेन्द्र को इस विचार को उन्होने जून 2005 में बीजापुर में रखा था। भाजपा मुख्यमंत्री रमनसिंह ने इसे मान लिया कि माओवादियों से लड़ने के लिये सरकार को अपनी जनता की शस्त्रों से लैस करना, इसके अलावा सलवा जुडुम के शांति सेनाओं को पुलिस द्वारा राइफल और मशीनगन चलाने गॉवों से लगभग 60,000 लोग छत्तीसगढ़ में बने 17 सलवा जुडुम शिविरों मं चले गये। 19 नवम्बर 2007 में कांग्रेस के प्रभावशाली नेता एवं सलवा जुडुम के अगुवा बुधराम राणा और उनके पुत्र कमलेश की हत्या माओवादियों द्वारा की गई। इससे इस अभियान को झटका लगा। उनके नाम नक्सलियों के हिट लिस्ट में था, इस घटना के बाद बीजापुर, भैरमगढ़, कोंट। सहित सभी आस—पास के क्षेत्र बंद कर दियें गये। बस्तर रेंज के महानिर्देशक का कहना था कि 'राणा की सुरक्षा के लिये उनके आवास में अंगरक्षक दियें गये थें।'

नक्सलियों ने दंतेवाड़ा से कई किलोमीटर दूर अबूझमाड़ को जहॉ भाजपा सरकार की उपस्थिति क्षीण है। अपना प्रभाव क्षेत्र बनाकर उस पर अपना नियंत्रण रखना हैं। दूसरी ओर इंद्रावती के पार वनों मे माओवादियों का समानातर शासन है। आज नक्सलवाद का रूप परिवर्तित हेा चुका यह नक्सलवाद चारू मजूमदार का सिद्धान्तवादी नक्सलवाद नही हैं बल्कि चीन की माओवादी विचार धारा जिसमें एल.टी.टी. ई की हिंसक विचार धारा एवं शस्त्र सम्मिलित है, वार ग्रुप ने एल टी.टी. ई. से कई तरह के सैन्य प्रशिक्षण लियें। शस्त्र चलाना एवं देशी बमों का उपयोग करना आदि। 2007 में नक्सलियों ने बीजापुर जिले के रानी बोदली पोस्ट पर आक्रमण कर 49 एस.पी.ओं सहित 55 लोगों को हमले की घटना थी। 2008 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के चित्रकोट प्रवास के समय नक्सलियों ने सी.आर.पी.एफ के वाहन को बारूदी सुरंग विस्फोट से उड़ाया , इस घटना में असिस्टेंट कमांडर सहित पॉच जवान मारे गये, विधानसभा चुनाव के समय भी डेढ़ दर्जन से अधिक लोग मारे गये। नक्सलियों ने चुनाव के समय पहली बार हेलिकॉप्टर को निशाना बनाया जिसमें एक जवान मारा गया।

2009 में अभी तक 14 पुलिस 39 सी.आर.पीएफ के जवान 17 एस. पी.ओं और 43 ग्रामीणों को नक्सलियों (माओवादियों) ने मौत के घाट उतारा 2009 में दी राजनांदगॉव जिले मदनवाड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ी नक्सली वारदात हुई जिसमें एस.पी.सहित 31 जवान शहीद हुये। पश्चिम बंगाल में लालगढ़ क्षेत्र में

नक्सलियों के कब्जे से पूरे देश में बवाल हुआ, लेकिन इससे बद्दतर स्थिति अबूझमाड़ की है, पुलिस का मानना है कि माड़ का 60 फीसदी क्षेत्र नक्सलियों के नियंत्रण है, जिसमें वे अपना प्रशिक्षण शिविर चलाने है जहॉ पर झारखण्ड उड़ीसा के माओवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रशिक्षण प्राप्त कर महाराष्ट्र व उड़ीसा में आक्रमण करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों की संख्या में हुई एवं उनके क्षेत्र का आकार भी बढ़ा है। गोदाम के बारसूर से लौट रहें सी.आर. पी.एफ जवानों के ट्रक को माओवादियों ने बारूदी सुरंग से उड़ाया जिसमें 08 जवान घायल हुये और 06 जवान शहीद हुये इस घटना के विरोध में बारसूर बंद रहा है। नक्सलियों (माओवादियों) के अभियान मं महिलाओं के प्रभाव व क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। पुलिस ने बताया कि इन दिनों नक्सली आंदोलनो की कमान महिला सदस्यों के हाथों मे है। जैसे कि राजनांदगांव के मानपुर में हुये नक्सली वारदांत की कमांडर महिला थी। नक्सली हमले के सम्बंध मे केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में बताया कि लगभग दस राज्यों में पिछलें साल नक्सली आक्रमण हुये जिसमें 3300 से अधिक लोग मारे जा चुके है। छत्तीसगढ़ बिहार, बंगाल, कर्नाटक, मे नक्सली हिंसा की 7,806 घटनायें हुई । सबसे अधिक मौते छत्तीसगढ़ में हुई यहॉं पर 2004 से 2008 के बीच 2,654 घटनायें जिसमें 1250 लोंग मारे गयें, छत्तीसगढ़ मे पिछले वर्ष 242,2007,में 369 और 2006 में 368 मौते हुयी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2008 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन मे नक्सली हिंसा को आंतरिक सुरक्षा के लिये संकट मानते हुये नक्सल विरोधी बल गठन का प्रस्ताव रखा जिसके सरकार द्वारा 10,000 कर्मियों की भर्ती विशेष प्रशिक्षण द्वारा। यह प्रस्ताव शीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा। जिससे 10 बटलियान तैयार की जायेगी जिसमें 2 वर्ष लगे। राज्यसभा में जब गृहमंत्री पी. चिंदबरम के सामने नक्सली हिसा का प्रश्न उठाया गया तक गृहमंत्री ने बताया कि वर्ष 2007,2008 में सुरक्षा बलों सबसे ज्यादा हानि छत्तीसगढ़ राज्य में हुई। इस समस्या के हल के लिये विशेष केन्द्रों की एक शाखा छत्तीसगढ़ में भी खुलेगी। निरंतर नक्सली हिंसा सम्बंधी वारदातो के बाद 24 जुलाई 2009 में विधानसभा सत्र में नक्सली मसले पर रमन –सरकार से विपक्षी दलो ने इस्तीफे की मॉग की, सदन में हंगॉमा किया गया, 27 विधायको ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, इस सत्र में 34 विधायको को सदन से निलबिम्त किया गया। इस समस्या के सम्बंध में मुख्यमंत्री रमनसिंह का कहना है कि विपक्ष रातों पर राजनीति करना बंद करे इसके निदान के लिये केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिये । वे चाहते है की नक्सली शस्त्र डालें एवं वार्ता द्वारा इस समस्या को सुलझाया जायें। राज्य गृहमंत्री कंवर का कहना है कि अतिरिक्त फोर्स के लिये केन्द्र सरकार से बात चल रही है। नक्सली निरतंर अपनी शक्ति व क्षेत्र में वृद्वि कर रहें हैं। उनका कहना है। कि पूरा अबूझमाड़ खाली है। नक्सलियों को हटाने के लिये बी.एस.एफ के नौ बटालियनों की मॉग केन्द्र सरकार से की गई। नक्सलियों की विचारधारा अब किसी आंदोलन से प्रेरित नही है, बल्कि अपराधियों का जमावड़ा है। वे वन अंचलों पर कब्जा करना चाहते है ताकि वहॉं से भरपूर वसूली कर सके। लोकतंत्र जिसका आधार है राजनीतिक समानता व स्वतंत्रता, आर्थिक समानता व स्वतंत्रता, सामाजिक समानता व स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक व्यवस्था पें सरकार एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्था हैं। जिसका दायित्व है जनता को विश्वसनीय बनाये रखना व प्रतिष्ठित करना अपनी साधन व सुविधओं के अनुसार राज्य अपने नागरिकों को अधिकार व सुविधायें प्रदान करती है। स्वतंजता प्राप्ति के 63 वें वर्ष बाद भी भारत वे कुछ क्षेत्रों का विकास निर्वाधगति से नही हो, सका संविधान की धारा 3 क से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था द्वारा राज्यों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विकसित करने हेतु नीतियॉं बनाने का अधिकार दिया गया। जिसके कियान्वयन द्वारा आर्थिक साधन एवं स्त्रोत एवं तीव्र गति से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास आवश्यक था भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिशाविहीन करने वाले विवाद भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति मं बाधक सिद्ध होते है। आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे होते है जो सम्यता के प्रकाश से दूर सूदूर पूर्व घने जंगलों मे निवास करते है" अपनी संस्कृति में रचे बसे है। लोकतांत्रिक विकास की दिशा में सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक योजनायें व कार्यक्रम जो उन्के अपने क्षेत्र से निकालकर सभ्यता की ओर ले जाता है, इन तक पहूॅच नही पाती ऐसी स्थिति का लाभ अलगाववादी तत्व उठाते है, देश के आंतरिक क्षेत्र में उपजे विवादो मं सबसे प्रमुख नक्सलवाद है।

विद्युत ट्रासफार्मर को ध्वस्त करना खदानों व औद्योगिक संस्थानो को बन्द कश्वाना, बेराजगारों को अपने हिंसात्मक कार्यवाहियों में सम्मिलित करना आदि राज्य की अर्थव्यवस्था को निर्वलकर केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था पर वजन बढ़ाता है। इस व्यवस्था के सुधार के लिये अतिरिक भार पंड़ता है केन्द्र सरकार पर ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

(1) योजना अप्रैल 2006 पृष्ठ 13 (2) इंडिया टुडे फरवरी 2008 पृष्ठ 37 (3) इंडिया टुडे 13 फरवरी 2008 पृष्ठ अ, 32 (4) दैनिक भास्कर 6 मार्च 2009 पृष्ठ 09 (5) दण्डकारण्य 17 जुलाई 2009 पृष्ठ 04 पृष्ठ 06 (6) नवभारत 29 जुलाई 2009 पृष्ठ 10 (7) नई दुनिया 7 जुलाई 2009 पृष्ठ 04 (8) दैनिक भास्कर 28 जुलाई 2009 पृष्ठ 01 (9) नई दुनिया 24 जुलाई 2009 पृष्ठ 01 (10) आउटलुक अगस्त 2009 पृष्ठ 23 (11) नईदुनिया 18 अगस्त 2009 पृष्ठ 01 (12) देशबन्धु 19 अगस्त 2009 पृष्ठ 04 (13) कुरूक्षेत्र पृष्ठ 38,39,40 (14) रिसर्च लिंक पृष्ठ 124,125 2006